

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 25, गुरुवार, शाके 1942-जुलाई 16, 2020 Asadha 25,, Thursday, Saka 1942-July 16, 2020	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-II

अधिसूचना

जयपुर, जून 26, 2020

जी.एस.आर.183 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

भाग-1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 2020 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 द्वारा शासित पदों पर, उन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषाएं :- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य/वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "समिति" से नियम 6 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;

(घ) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग-4 में यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है ;

(ङ) "विद्युत निरीक्षणालय" से राजस्थान विद्युत निरीक्षणालय अभिप्रेत है ;

(च) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ;

- (छ) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित किये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन नियमित चयन के आधार पर सेवा में के किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (ज) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (झ) "सेवा" से राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) अभिप्रेत है ;
- (ञ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ;
- (ट) "अधिष्ठायी नियुक्ति" से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गयी कोई नियुक्ति भी है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो ;

टिप्पण : इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से किये गये सम्यक् चयन के अन्तर्गत, अर्जेंट/अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गयी भर्ती आयेगी ; और

(ठ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन .- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग-2

संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या .- (1) सेवा में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची-I के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट है।

(2) सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु,-

- (क) सरकार आवश्यक प्रतीत होने पर किसी भी स्थायी या अस्थायी पद (पदों) का समय-समय पर, सृजन कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद (पदों) को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी ; और

- (ख) नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को, समय-समय पर, रिक्त या प्रास्थगित रख सकेगा या समाप्त या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

5. सेवा का आरम्भिक गठन .- सेवा निम्नलिखित से गठित होगी,-

- (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पद (पदों) को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति ;
- (ख) इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व सेवा में सम्मिलित पद पर नियमित रूप से भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति ; और
- (ग) नियम 32 के अधीन किसी अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार, सेवा में के पदों पर भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति।

भाग-3

भर्ती

6. **भर्ती की रीतियां .-** (1) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में सम्मिलित पदों पर भर्ती, इन नियमों के भाग-4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति, जिसने आपातकाल के दौरान थल सेना/वायुसेना/नौसेना में कार्यग्रहण किया हो, की भर्ती, वरिष्ठता और स्थायीकरण इत्यादि का विनियमन सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी आदेशों और अनुदेशों द्वारा किया जायेगा, परन्तु ऐसा विनियमन, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उक्त विषय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी न्यायालय या अधिकरण के मध्यक्षेप के सम्यक रूप से स्वीकृत पदों पर अनियमित रूप से नियुक्त किये गये हों और 10-04-2006 को दस वर्ष की सेवावधि पूर्ण कर ली हो, और इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को इस रूप में निरन्तर कार्य कर रहे हों, उनकी स्क्रीनिंग निम्नलिखित रूप से गठित समिति द्वारा की जायेगी,-

- (i) प्रमुख सचिव/शासन सचिव, ऊर्जा विभाग ;
- (ii) प्रमुख सचिव/शासन सचिव, वित्त विभाग या उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका नामनिर्देशिती; और
- (iii) प्रमुख सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग या उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका नाम निर्देशिती :

परन्तु वे उनकी प्रारम्भिक अनियमित नियुक्ति की तारीख को नियमों के अनुसार नियुक्ति के पात्र हों, और स्क्रीनिंग के समय रिक्ति उपलब्ध हो। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति के नियुक्ति आदेश

जारी करेगा, जिसे स्क्रीनिंग समिति द्वारा उपयुक्त न्यायनिर्णीत किया जाता है और नियुक्ति, ऐसा नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की तारीख से लागू होगी।

7. मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/पैरा-मिलिटरी कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.- (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, सुसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताओं और अन्य सेवा-शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग की सहमति के अध्यक्षीन रहते हुए,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा पे मैट्रिक्स, समय-समय पर यथा संशोधित, के लेवल एल-9 तक के पदों की भरे जाने वाली रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके;
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा पे मैट्रिक्स, समय-समय पर यथा संशोधित, के लेवल एल-10 तक के पदों की भरे जाने वाली रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके; और
- (iii) सीधी भर्ती द्वारा पे मैट्रिक्स, समय-समय पर यथा संशोधित, के लेवल एल-9 तक के पदों की भरे जाने वाली रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य, जो 01.01.1971 से 31.03.1999 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा गया था या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके, भर सकेगा:

परन्तु,-

- (i) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा; और
- (ii) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी का कार्मिक, जिसकी मृत्यु हो गयी है या जो स्थायी रूप से अशक्त हो गया है, की विधवा या बच्चे तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के कार्मिक के आश्रित को नियुक्ति केवल तब दी जायेगी जब उनमें से किसी एक ने भारत सरकार के विद्यमान संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं पा ली है।

(3) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के कार्मिक की मृत्यु के समय उनका कोई भी अन्य आश्रित केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय/राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कानूनी बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित हो तो ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं अपने लिए रोजगार चाहती है।

(4) ऐसा आश्रित इस प्रयोजन के लिए आवेदन सशस्त्र बलों के मामले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को और पैरा-मिलिटरी बलों के मामले में पैरा-मिलिटरी यूनिट के कमान अधिकारी को सम्बोधित करेगा जो उस यूनिट के प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो जहां सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों का मृत/स्थायी रूप से अशक्त सदस्य मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के समय सेवारत था। ऐसे आवेदन पर, सामान्य भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जायेगा कि आश्रित ऐसे पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, सिवाय चतुर्थ श्रेणी नियुक्ति के, जिसके लिए शैक्षिक अर्हता शिथिल की जायेगी, तथा पद के लिए विहित आयु सीमा पूरी करता है और सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्हित भी है।

(5) ऐसे आश्रित का आवेदन, आश्रित द्वारा रखी जाने वाली अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में, आवेदन खण्ड आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि खण्ड आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो आवेदन, नियुक्ति देने के लिए खण्ड आयुक्त द्वारा सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) आवेदन में निम्नलिखित सूचनाएं अंतर्विष्ट होंगी :-

- (i) सशस्त्र बल/पैरा-मिलिटरी बलों के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम ;
- (ii) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के पूर्व कार्यरत था/थी ;
- (iii) युद्ध में हताहत या स्थायी रूप से अशक्त घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु की तारीख और स्थान ; और
- (iv) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हता और मृतक के साथ उसका सम्बन्ध (प्रमाणपत्रों सहित)।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए ,-

- (क) "सशस्त्र बल" से संघ की थल सेना, नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत है ;
- (ख) "आश्रित" से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति का पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिक/पैरा-मिलिटरी कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित थे ;

टिप्पण: दत्तक पुत्र/पुत्री से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति द्वारा उसके जीवन में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है।

(ग) "पैरा-मिलिटरी बल" से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और कोई अन्य पैरा-मिलिटरी बल, जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत है ; और

(घ) "स्थायी रूप से अशक्त" व्यक्ति से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो दिव्यांगजन व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) में यथा उपबंधित "बैंच मार्क दिव्यांग व्यक्ति" पद की परिभाषा के अधीन आता है।

8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा।

(2) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी कौनसी रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(3) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती के लिए विहित रोस्टर के अनुसार की जायेंगी।

(4) किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती तीन भर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी:

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में

आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्षों में उपलब्ध हो।

9. पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। किसी वर्ष-विशेष में पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, 10 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' में, वह व्यक्ति, जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई, उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। 'आय' में समस्त स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय होगी।

11. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह महिला-अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष-विशेष में या तो विधवा या विछिन्न विवाह-महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विछिन्न विवाह- महिलाओं से विषर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह-अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पश्चात्पूर्वी वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह-महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए

आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह-महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

12. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण .- उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष में सेवा के अधीन सीधी भर्ती के लिए चिह्नित, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों के उपलब्ध न होने की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्पूर्ति वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण : "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें राज्य के ऐसे खिलाड़ी सम्मिलित हैं जिन्होंने,-

- (i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो ;

या

- (ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो ;

या

- (ii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

- (iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

13. राष्ट्रीयता.- सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह;

- (क) भारत का नागरिक हो ; या

- (ख) नेपाल का प्रजाजन हो ; या
- (ग) भूटान का प्रजाजन हो ; या
- (घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो ; या
- (ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो :

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों से संबंधित कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

14. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु-सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

15. रिक्तियों का अवधारण.- (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद इस नियम या अनुसूची में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उसी रीति से भरी जायेंगी।

16. आयु.- अनुसूची में प्रगणित किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम तारीख के ठीक पश्चात् आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु -

(i) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को -

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;

(ख) सामान्य प्रवर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ; और

- (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक, शिथिल किया जायेगा।
- (ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;
- (iii) उस भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा;
- (iv) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित न्यूनतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
- (v) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
- (vi) विधवाओं और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न-विवाह के मामले में उसे विवाह- विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

- (vii) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में होते, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे।
- (viii) रिजर्विस्ट अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी ; और

- (ix) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

17. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हता और अनुभव.- अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों के लिए सीधी भर्ती का अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखेगा :-

- (i) अनुसूची-I के स्तम्भ संख्यांक 5 में अधिकथित अर्हता और अनुभव; और
- (ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान:

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के लिए इन नियमों या अनुसूची में यथा-उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु उसे ,-

- (i) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व ;
- (ii) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व ; और
- (iii) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व;

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

18. चरित्र.- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या विद्यालय से संबद्ध न हों और न उसके संबंधी हों।

टिप्पण :- (1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में, सच्चरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्गस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलन से नहीं है, जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

- (2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्कर्तृ सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्गुह्य नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे 'पश्चात्कर्तृ देखरेख गृह' के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।
- (3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्गुह्य है, सिद्धदोष ठहराया गया है, पश्चात्कर्तृ देखरेख गृह के अधीक्षक का या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्कर्तृ देखरेख गृह में अपने पश्चात्कर्तृ सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

19. शारीरिक उपयुक्तता.- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पदों के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

20. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.- कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेजों जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी है या बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त:

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ;और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा, या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

21. संयाचना.- इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।

भाग-4

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

22. प्रतियोगी परीक्षा, परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी और परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण.- (1) सेवा में के सम्मिलित पद पर सीधी भर्ती, अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अनुसार लिखित प्रतियोगीपरीक्षा के माध्यम से की जायेगी।

(2) लेवल-5 में पे मैट्रिक्स समय-समय पर यथा संशोधित कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक और हैल्पर (तकनीकी पद से संलग्न) के पद के लिए परीक्षा बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित की जायेगी।

23. आवेदन आमंत्रित करना.- सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और उस पद के पे मैट्रिक्स के लेवल में वेतन जैसा कि विज्ञापन में अन्यत्र उल्लिखित है, इन नियमों में उल्लिखित परीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा:

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी, यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

24. सीधी भर्ती की आवृत्ति.- अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती तब तक वर्ष में कम से कम एक बार की जायेगी जब तक कि सरकार यह विनिश्चय नहीं कर ले कि इनमें से किसी पद के लिए किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती आयोजित नहीं की जायेगी।

25. आवेदन का प्ररूप.- आवेदन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्ररूप में किया जायेगा और वह बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके, जो बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय नियत करे, प्राप्त किया जा सकेगा।

26. आवेदन फीस.- सेवा में के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियत फीस, ऐसी रीति से, जो वह उपदर्शित करे, संदत करेगा।

27. आवेदनों की संवीक्षा.- बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी अपने द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, उसके द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा:

परन्तु किसी अभ्यर्थी के पात्र होने या अन्यथा के बारे में बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

28. बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें.- बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, एकसूची तैयार करेगा, योग्यता क्रम में व्यवस्थित करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहा है। तथापि, अजा/अजजा प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम 5 प्रतिशत तक के अंकों का शिथिलीकरण लागू होगा:

परन्तु बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम प्रवर्गवार आरक्षित सूची में रख सकेगा। अध्यपेक्षा किये जाने पर, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यता क्रम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको मूल सूची बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर-भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को की जा सकेगी।

29. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.- (1) कोई पुरुष या महिला अभ्यर्थी, जिसकी/जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय उस दशा के जब नियुक्ति प्राधिकारी, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय उस दशा के जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार से परामर्श से अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय या तत्पश्चात् किसी समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु,-

- (i) दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं
- (ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्पूर्वी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
- (iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःषक्तता से ग्रस्त हो।
- (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- (v) इस उप-नियम के उपबंध राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के उपबंधों के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे ।

30. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.- नियम 8,9,10,11 और 12 के उपबंधों के अध्याधीन नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 28 के अधीन तैयार की गयी सूची में योग्यता क्रम में अभ्यर्थियों का चयन करेगा:

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग-5**नियुक्ति, वरिष्ठता, परिवीक्षा और स्थायीकरण**

31. सेवा में नियुक्ति.- सीधी भर्ती द्वारा सेवा में के पदों पर नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, नियम 28 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यताक्रम में की जायेगी।

32. अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति.- (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, सरकार द्वारा या, यथास्थिति, नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा में सीधी भर्ती द्वारा, जहां ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबंधों के अधीन उपबन्धित हो, किसी व्यक्ति को जो उस पद पर नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त करके भरा जा सकेगा:

परन्तु ऐसी कोई नियुक्ति सहमति के लिए, सरकार को मामला निर्देशित किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी और सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।

(2) पात्रता की अपेक्षा पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन अपेक्षित पात्रता की शर्त होते हुए भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह निदिष्ट करे, अर्जेंट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन यथा-अपेक्षित सहमति के अध्यधीन होंगी।

33. वरिष्ठता.- सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेंट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी:

परन्तु , -

- (i) किसी प्रवर्ग-विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी होने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या दीर्घतर कालावधि, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जाये, सेवाग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम इन नियमों के नियम 28 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे गये हैं;
- (ii) ऐसे चयन के, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्पूर्वी चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये जाते हैं; और

- (iii) नियम 6 के उप-नियम (3) के परन्तुक के अधीन स्क्रीन किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनकी अनियमित नियुक्ति के पश्चात् उनकी निरन्तर सेवा अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी। ये व्यक्ति रैंक में उन व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व नियमित रूप से नियुक्त किये गये हैं।

34. परिवीक्षा की कालावधि.- (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा:

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

35. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.- (1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में के किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा नियमित भर्ती के पश्चात् उसके परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने की दशा में दो वर्ष के परिवीक्षाकाल की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात् छह मास की कालावधि के भीतर या उसके पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने की दश में सेवा में एक वर्ष की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा, यदि -

- (i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता;
- (ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता हो; और
- (iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो, बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटा दिये जाने का दायी होगा जिस रीति से

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह उस अधिष्ठायी या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवाकाल के दौरान संसूचित न किये गये हों।

(4) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भर्ती की किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारंभिक गठन के समय की गयी नियुक्ति;

(ख) उस पद पर नियुक्ति, जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हो, यदि पद आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो तो आयोग के परामर्श से भर्ती ;

(ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हों; और

(घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगे:

परन्तु इसमें ऐसी अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्यधीन हो।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इन नियमों के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

36. परिवीक्षा के दौरान असंतोषप्रद प्रगति- यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा जिस पर उसका, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व, नियमित रूप में चयन किया गया था या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त

कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगा:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि तक बढ़ा सकेगा।

37. स्थायीकरण.- नियम 34 के अधीन परिवीक्षा पर रखे गये किसी व्यक्ति को उसके परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि,-

- (क) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और ऐसा प्रशिक्षण, जैसा कि सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो;
- (ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

भाग-6

वेतन

38. वेतनमान.- सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का पे मैट्रिक्स (समय-समय पर यथा संशोधित) के लेवल में वेतन वह होगा जो नियम 40 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किया जाये।

39. परिवीक्षा के दौरान वेतन.- सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दरों पर मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा:

परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित कर्मचारियों को परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थियों के रूप में सेवा के दौरान उस पद के पे मैट्रिक्स के विद्यमान लेवल में उसके स्वयं के पे मैट्रिक्स के लेवल में परिलब्धियां या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

40. वेतन, छुट्टी, भत्ते, अंशदायी पेंशन, पेंशन आदि का विनियमन.- इन नियमों में यथा-उपबंधित के सिवाय सेवा के सदस्यों का वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी:-

- (i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथासंशोधित;
- (ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय-समय पर यथासंशोधित ;

- (iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथासंशोधित;
- (iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय-समय पर यथासंशोधित;
- (v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय-समय पर यथासंशोधित;
- (vi) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 समय-समय पर यथासंशोधित ;
- (vii) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय-समय पर यथासंशोधित;
- (viii) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय-समय पर यथासंशोधित; और
- (ix) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, समय-समय पर यथासंशोधित; और
- (x) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त कोई भी अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों।

41. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.- अपवादिक मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग की सहमति से, आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों से, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी:

परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले प्रशासनिक विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

परन्तु यह कि इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा।

परन्तु यह और कि जहां किसी पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की विहित कालावधि 6 वर्ष से कम है वहां प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग और प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासनिक विभाग से गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति उन मामलों पर विचार करेगी जहां 45 प्रतिशत या उससे अधिक पद रिक्त हैं । समिति अनुभव में शिथिलीकरण की इतनी मात्रा

सुझाने के लिए सशक्त होगी जो ऐसे मामलों में, पदोन्नति वाले पदों में रिक्तियों की बड़ी संख्या के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए, इस शर्त के अध्याधीन प्रदान की जायेगी कि अनुभव में ऐसा शिथिलीकरण दो वर्ष से अधिक न हो।

42. शंकाओं का निराकरण.- यदि इन नियमों के लागू होने और व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

43. निरसन और व्यावृत्तियां.- इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित समस्त नियम और आदेश, जो इन नियमों का प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

अनुसूची-1

क्र.स.	पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती की रीति		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी भर्ती	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक	100 प्रतिशत	-	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता। या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा	-	-	-
2.	हेल्पर (तकनीकी पद से संलग्न)	100 प्रतिशत	-	सैकण्डरी के साथ राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र या विद्युत ट्रेड में आई.टी.आई. प्रमाणपत्र।	-	-	-

अनुसूची-II**(क) कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक के पद के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:**

1. कम्प्यूटर आधारित "लिखित प्रतियोगी परीक्षा" ऑनलाइन रीति के माध्यम से संचालित की जायेगी। प्रश्नपत्र दो घण्टे का होगा और उसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुविकल्पित) प्रश्न होंगे।

2. प्रश्नपत्र निम्नलिखित रूप से दो प्रकार का होगा:-

भाग क: 60 प्रतिशत अधिमान

परीक्षा का मानक और पाठ्य विवरण विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्तर का होगा और इसका संक्षिप्त-सार परीक्षा के पूर्व अधिसूचित किया जा सकेगा।

भाग ख: 40 प्रतिशत अधिमान

- (i) तार्किकता और मानसिक योग्यता
- (ii) गणित
- (iii) सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान
- (iv) सामान्य हिन्दी
- (v) सामान्य अंग्रेजी

इस भाग के विस्तार का संक्षिप्त-सार अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए नीचे दिया जा रहा है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है:-

- (i) **तार्किकता और मानसिक योग्यता:-** विश्लेषणात्मक तार्किकता, अंक श्रृंखला, शब्द श्रृंखला, असंगत अलग कीजिए, कोडिंग-डिकोडिंग, आकार और दर्पण छवि, घड़ियां इत्यादि।
- (ii) **गणित:** गणित (कक्षा-12 स्तर) मा.शि.बो. या राजस्थान बोर्ड।
- (iii) **सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान:-** राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय महत्व के मामलों को सम्मिलित करते हुए हाल में समाचारों में रहे व्यक्ति और स्थान, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, खेलकुद, विज्ञान, भारतीय इतिहास, नागरिकशास्त्र, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि।
- (iv) **सामान्य हिन्दी:-** हिन्दी व्याकरण और भाषा (कक्षा-ग् स्तर) मा.शि.बो. या राजस्थान बोर्ड।
- (v) **सामान्य अंग्रेजी:-** अंग्रेजी व्याकरण और भाषा (कक्षा-ग् स्तर) के मा.शि.बो. या राजस्थान बोर्ड।

3. प्रश्नपत्र (भाग-ख के अनुभाग "सामान्य हिन्दी" और "सामान्य अंग्रेजी" को छोड़कर) द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में होगा किंतु निर्वचन या छपाई की

किसी गलती के संबंध में भ्रम/विरोधाभास की दशा में प्रश्नपत्र का अंग्रेजी भाग लागू होगा।

- 4 किसी गलत अन्तर के लिए 'नकारात्मक' अंकन नहीं होगा।
5. यदि परीक्षा एक या अन्य कारण से एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है तो विभिन्न सत्रों में उपयोग की जाने वाली बैटरी के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर के लिए समायोजित करने के लिए स्कोर को बराबर किया जाएगा।
6. नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड, सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न की पहचान करने के लिए, वैयक्तिक अभ्यर्थियों के प्रत्युत्तर (उत्तरों) का अन्य अभ्यर्थियों के उत्तरों के साथ विश्लेषण करेगा। यदि यह परिणाम/निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्युत्तर शेयर किये गये हैं और अभिप्राप्त स्कोर वास्तविक/विधि मान्य नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थितता रद्द करने का अधिकार आरक्षित रखता है और ऐसे अभ्यर्थी (निरर्हित) का परिणाम रोक लिया जायेगा।
7. ऑनलाईन परीक्षा का स्कोर निम्नलिखित प्रक्रिया अंगीकृत करके अभिप्राप्त किया जायेगा:-
 - (i) बहुविकल्पीय परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा जिन प्रश्नों के सही उत्तर दिये गये हैं, उनकी संख्या को "सही स्कोर" की गणना करने के लिए विचार में लिया जायेगा।
 - (ii) अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार प्राप्त 'सही स्कोर' को 'समान स्कोर' तक लाने के लिए, विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कठिनाई के स्तर, यदि कोई हो, के सूक्ष्म अंतर का ध्यान रखा जायेगा। किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अभिप्राप्त स्कोर का सभी प्रकार के स्कोर के संवितरण पर विचार करते हुए आधार प्ररूप के समान किया जाएगा।
 - (iii) कुल अंकों की गणना दो अंकों तक दशमलव बिंदु के साथ की जाएगी।
8. लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्ण अंक 40 प्रतिशत होंगे। तथापि, अजा/अजजा प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों को 5 प्रतिशत तक शिथिल किया जायेगा।
9. कोई 'साक्षात्कार' नहीं होगा।

(ख) हैलपर के पद के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण (तकनीकी पद से संलग्न):

1. लिखित प्रतियोगी परीक्षा संचालित की जायेगी। अधिकतम 250 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घण्टे की होगी। प्रश्नपत्र के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

विषय	पाठ्य विवरण और स्तर	प्रश्न	अधिकतम अंक	समय
भाग-क सामान्य ज्ञान	समसामयिकी, सामान्य विज्ञान और प्राथमिक गणित, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भूगोल और प्राकृतिक स्रोत, कृषि और आर्थिक विकास। इतिहास और संस्कृति।	50	50	2 घण्टे
भाग-ख तकनीकी ज्ञान/ कौशल	पाठ्य विवरण और स्तर इलैक्ट्रिकल ट्रेड में आई.टी.आई. के स्तर का होगा	100	200	

2. प्रश्नपत्र 'वस्तुनिष्ठ' (बहुविकल्पिय) प्रकार का होगा। भाग-क में प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और भाग-ख में प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा। प्रश्नपत्र द्विभाषी अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में होगा। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

3. अभ्यर्थियों का चयन, लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

4. लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्ण अंक 40 प्रतिशत होंगे। तथापि, अजा/अजजा प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों को 5 प्रतिशत तक शिथिल किया जायेगा।

5. कोई 'साक्षात्कार' नहीं होगा।

6. यदि लिखित प्रतियोगी परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी वरीयता उनकी जन्म की तारीख के अनुसार विनिश्चित की जायेगी अर्थात् आयु में बड़ा अभ्यर्थी वरीयताक्रम क्रम में उच्चतर होगा।

[एफ. 1(3) डी ओ पी/ए-II/2020]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

शासन उप सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr-II

NOTIFICATION

Jaipur, June 26, 2020

G.S.R. 183.-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules regulating the recruitment to posts in and the conditions of service of persons appointed to the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Electrical Inspectorate Branch), namely:-

PART – I

General

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Electrical Inspectorate Branch) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with immediate effect.

(3) These rules shall not apply to the posts Governed by the Rajasthan Scheduled Areas Subordinate, Ministerial and Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2014, except as provided in those rules.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Appointing Authority" means the Chief/Senior Electrical Inspector;
- (b) "Board" means the Rajasthan Staff Selection Board;
- (c) "Committee" means the committee referred to in sub-rule (3) of rule 6;
- (d) "Direct recruitment" means recruitment made in accordance with the procedure as prescribed in Part-IV of these rules;
- (e) "Electrical Inspectorate" means the Rajasthan Electrical Inspectorate;
- (f) "Government" means the Government of Rajasthan;
- (g) "Member of the Service" means a person appointed to a post in the service on the basis of regular selection under the provisions of these rules or the rules /orders superseded by these rules;
- (h) "Schedule" means the schedule appended to these rules;
- (i) "Service" means the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Electrical Inspectorate Branch) ;
- (j) "State" means the State of Rajasthan;
- (k) "Substantive appointment" means an appointment made under the provisions of these rules to a substantive vacancy after due selection by any of the methods of recruitment prescribed under these rules and includes an appointment on probation or as a probationer trainee followed by confirmation on the completion of the probationary period;

Note: Due selection by any methods of recruitment prescribed under these rules shall include recruitment either on initial constitution of service or in accordance with the provisions of any rules promulgated under proviso to Article 309 of the Constitution of India, except an urgent /temporary appointment; and

- (l) "Year" means financial year.

3. Interpretation.- Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these rules as it applies for the interpretation of a Rajasthan Act.

PART – II

CADRE

4. Composition and strength of the service.- (1) The nature of posts included in the service shall be as specified in column number 2 of the Schedule I.

(2) The strength of the posts in the service shall be such as may be determined by the Government, from time to time:

Provided that,-

- (a) the Government may create any post(s), permanent or temporary, from time to time, as may be considered necessary and may abolish any such post(s) in the like manner without thereby entitling any person to any compensation; and
- (b) the Appointing Authority may leave unfilled or hold in abeyance or abolish or allow to lapse any permanent or temporary post, from time to time, without thereby entitling any person to any compensation.

5. Initial Constitution of the service.- The service shall consist of ,-

- (a) all persons holding substantively the post(s) specified in the Schedule-I, on the date of commencement of these rules;
- (b) all persons regularly recruited to the post included in the service before the commencement of these rules; and
- (c) all persons recruited to the post in the service in accordance with the provisions of these rules except urgent temporary appointment under rule 32.

PART – III
RECRUITMENT

6. Method of recruitment.- (1) Recruitment to the posts included in the service after the commencement of these rules shall be made by direct recruitment in accordance with the procedure laid down in Part-IV of these rules.

(2) Notwithstanding anything contained in these rules the recruitment, seniority and confirmation etc. of a person who joins the Army/Air Force/ Navy during an Emergency shall be regulated by such orders and instructions as may be issued by the Government, from time to time, provided that these are regulated mutatis-mutandis according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

(3) The persons, irregularly appointed on duly sanctioned posts and completed ten years service on 10-04-2006, without intervention of any court or tribunal, and continuously working as such on the date of commencement of these rules, shall be screened by a committee consisting of ,-

- (i) Pr. Secretary/Secretary to the Government, Energy Department;
- (ii) Pr. Secretary/Secretary to the Government, Finance Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary; and
- (iii) Pr. Secretary/Secretary to the Government, Department of Personnel or his nominee not below the rank of Deputy Secretary,

Provided they were eligible for appointment, as per rules on the date of their initial irregular appointment and vacancy is available at the time of screening. The Appointing Authority shall issue appointment order of the person, who is adjudged suitable by the screening committee and appointment shall be effective from the date of issue of such appointment order.

7. Compassionate Appointment of Dependents of the Deceased / Permanently Incapacitated Armed Forces Service Personnel/ Paramilitary Personnel.- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Appointing Authority may fill the vacancies of the ,-

- (i) post upto Level in Pay Matrix L-9, as amended from time to time, to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground, one of the dependents of a member of Armed Forces/Para Military Forces belonging to the State who becomes permanently incapacitated on or after 1.4.1999 in any defence operations including counter insurgency operations and operations against terrorists;
- (ii) post upto Level in Pay Matrix L-10, as amended from time to time, to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground, one of the dependents of a member of Armed Forces/Para Military Forces belonging to the State who dies on or after 1.4.1999 in any defence operations including counter-insurgency operations and operations against terrorists; and
- (iii) post upto Level in Pay Matrix L-9, as amended from time to time, to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground, one of the dependent of a member of Armed Forces belonging to the State, who died or was permanently incapacitated in war or any defence operations including counter insurgency operations and operations against terrorists during the period from 1.1.71 to 31.3.1999,

Subject to fulfilment of the educational qualifications and other service conditions prescribed under the relevant rules and with the concurrence of Department of Personnel:

Provided that,-

- (i) if the Armed Forces/Para Military Personnel who are permanently incapacitated are capable of and desirous of obtaining employment for themselves under the State Government, employment shall be given to them; and
- (ii) if the widow or the children of the Armed Forces/Para Military Personnel who are killed or permanently incapacitated are not in a position to take up employment immediately, employment will be given to them on acquiring of eligibility for appointment.

(2) Appointment shall be given to a dependent of Armed Forces/Para Military Personnel only if any of them has not got appointment on any post under the provisions of concerned service rules prevailing in the Government of India.

(3) Appointment shall not be given to such dependent if any of the other dependent of the Armed Forces/Para Military Personnel is already employed on regular basis under the Central/any State Government or Statutory Board Organisation/Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central/any State Government at the time of death of the Armed Forces/Para Military Personnel:

Provided that this condition shall not apply where the widow seeks employment for herself.

(4) Such dependent shall address an application for the purpose to the Zila Sainik Kalyan Adhikari in the case of Armed Forces and the Officer Commanding the Para-Military Unit for Para Military Forces duly verified by the Head of the Unit where the deceased/permanently incapacitated member of the Armed Forces/Para Military Forces was serving at the time of death/becoming permanently incapacitated. The application shall be considered in relaxation of the normal recruitment rules subject to the condition that the dependent fulfills the academic qualifications and experience, except for appointment to Class-IV for which educational qualification shall be relaxed, and age limit prescribed for the post and is also otherwise qualified for Government Service.

(5) The application of such dependent shall be forwarded to the District Collector concerned for suitable appointment according to the qualifications possessed by the dependent. In the event of non-availability of vacancy in the District concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who shall arrange appointment in any District under his jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner then the application shall be referred by the Divisional Commissioner to Government in the Department of Personnel for providing appointment.

(6) The application shall contain the following information:-

- (i) Name and designation of the deceased/Permanently incapacitated Armed Force/Para-Military Force personnel;
- (ii) Unit in which he/she was working prior to death/becoming permanently incapacitated;
- (iii) Date and place of death with death certificate issued by the Authority competent to declare him a battle casualty or becoming permanently incapacitated; and
- (iv) Name, date of birth, educational qualification of the applicant and his/her relation with the deceased (with certificates).

Explanation: For purpose of this rule,-

- (a) “Armed Force” means the Army, Navy and Air Force of the Union;
- (b) “Dependent” means the spouse of the deceased /permanently incapacitated person, son/adopted son, unmarried daughter/unmarried adopted daughter who were wholly dependent on the deceased/permanently incapacitated Armed Forces Service Personnel/Para Military Personnel ;

Note: Adopted son/daughter means legally adopted son/daughter by the deceased/permanently incapacitated person during his/her life.

- (c) "Para-Military Forces" means the Border Security Force, Central Reserve Police Force, Indo Tibetan Border Police and any other Para-Military Force, as may be notified by Central and State Government, from time to time; and
- (d) "Permanently incapacitated" means a person who is covered under the definition of the term person with bench mark disabilities as provided in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016).

8. Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.-

- (1) Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be in accordance with the provision of law in force at the time of recruitment.
- (2) In filling the vacancies so reserved the eligible candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list prepared for direct recruitment by the Board or the Appointing Authority, as the case may be, irrespective of their relative ranks as compared with other candidates.
- (3) Appointments shall be made strictly in accordance with the roster prescribed for direct recruitment.
- (4) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates amongst the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for direct recruitment, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward to the subsequent three recruitment years. After the expiry of three recruitment years, such carried forward vacancies, shall be filled in accordance with the normal procedure:

Provided that if recruitment is not held in any recruitment year, such recruitment year shall not be counted for the purpose of this sub-rule.

Provided further that filling up of the vacancies in accordance with the normal procedure under this sub-rule shall not affect the reservation of posts as per the post based roster and vacancies on the reserved posts available in the roster may be filled in from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for which such vacancy is available in subsequent years.

9. Reservation of vacancies for the Backward Classes and More Backward Classes.- Reservation of vacancies for the Backward Classes and More Backward Classes shall be in accordance with the provision of law in force at the time of direct recruitment. In the event of non-availability of eligible and suitable candidates amongst the Backward Classes and More Backward Classes in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

10. Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections.- Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections shall be 10% in direct recruitment in addition to

the existing reservation. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate amongst Economically Weaker Sections in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

Explanation: For the purpose of this rule 'Economically Weaker Sections' shall be the person who are bonafide resident of Rajasthan and not covered under the existing scheme of reservations for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, the More Backward Classes and whose family has gross annual income below rupees 8.00 lakh. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income for all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application.

11. Reservation of vacancies for women candidates.- Reservation of vacancies for woman candidates shall be 30% category wise in direct recruitment, out of which one third shall be for widows and divorced women candidates in the ratio of 80:20. In the event of non availability of eligible and suitable candidates, either in widows or in divorcee, in a particular year, the vacancies may first be filled by interchanged, i.e. vacancies reserved for widow to the divorcees or vice versa. In the event of non availability of sufficient widow and divorcee candidates, the unfilled vacancies, shall be filled by other women of the same category and in the event of non availability of eligible and suitable women candidates, the vacancies so reserved for them shall be filled up by male candidates of the category for which vacancy is reserved. The vacancies so reserved for women candidates shall not be carry forwarded to the subsequent year. The reservation for women including widows and divorcee women shall be treated as horizontal reservation, within the category, i.e. even the women selected in general merit of the category shall first be adjusted against the women quota.

Explanation: In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the competent Authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce.

12. Reservation of vacancies for Outstanding sportspersons.- Reservation of vacancies for outstanding sportspersons shall be 2% of the total vacancies outside the purview of the Rajasthan Public Service Commission in that year earmarked for direct recruitment. In the event of non-availability of the eligible and suitable sportspersons in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure and such vacancies shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for sportspersons shall be treated as horizontal reservation and it shall be adjusted in the respective category to which the sportspersons belong.

EXPLANATION: "Outstanding sportspersons" shall mean and include the sportspersons belonging to the State, who,-

- (i) represented Indian Team in Individual or in Team event in any International Tournament of any Sports and Games, recognized by the Indian Olympic Association or concerned recognized National Sports Federation;

or

- (ii) represented Indian Team in Individual or in Team event in any International Tournament of any Sports and Games, recognized by the Indian School Sport Federation or concerned recognized National School Games Federation;

or

- (iii) medal Winner in the Individual or in Team event in any National Tournament of any Sports and Games, recognized by the Indian Olympic Association or concerned recognized National Sports Federation;

or

- (iv) medal Winner in the All India Inter University Tournament in Individual event or in Team event in the any Sports and Games, recognized by Indian Universities Association.

13. Nationality.- A candidate for appointment to the service must be ;

- (a) A citizen of India; or
- (b) A subject of Nepal; or
- (c) A subject of Bhutan; or
- (d) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (e) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Counties of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government in the Department of Home Affairs and Justice after proper verification.

14. Conditions of eligibility of person migrated from other countries to India.-

Notwithstanding anything contained in these rules, provisions regarding eligibility for recruitment to the service with regard to nationality, age limit and fee or other concessions to a person who may migrate from other countries to India with the intention of permanently settling in India shall be regulated by such orders or instructions as may be issued by the State Government, from time to time and the same shall be regulated mutatis mutandis according to the instruction issued on the subject by the Government of India.

15. Determination of vacancies.- (1) Subject to the provisions of these rules, the Appointing Authority shall determine on 1st April every year, the actual number of vacancies occurring during the financial year.

(2) Where a post is to be filled in by a single method as prescribed in the rule or Schedule, the vacancies so determined shall be filled in by that method.

16. Age.- A candidate for direct recruitment to a post enumerated in Schedule must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 40 years on the first day of January next following the last date fixed for receipt of applications:

Provided that,-

- (i) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by,-
 - (a) 5 years in the case of male candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and More Backward Classes;
 - (b) 5 years in the case of woman candidates belonging to General Category and Economically Weaker Sections; and
 - (c) 10 years in the case of woman candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and More Backward Classes.
- (ii) the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under these rules;
- (iii) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under these rules;
- (iv) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the Service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed above by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit;
- (v) the Released Emergency Commissioned Officers and Short Services Commissioned after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Board or the Appointing Authority as the case may be had they been eligible as such at the time of their Joining the Commission in the Army.
- (vi) there shall be no upper age limit in the case of widows and divorced woman;

Explanation: In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce;

- (vii) the persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Board or Appointing Authority, as the case may be and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment;
- (viii) the upper age limit mentioned above shall be 50 years in the case of ex-service personnel and the reservists, namely the defence service personnel who were transferred to the reserve; and
- (ix) if a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/she is not over-age by more than 3 years.

17. Academic and technical qualification and experience.- A candidate for direct recruitment to the posts specified in the Schedule shall possess,-

- (i) the qualifications and experience as laid down in column number 5 of the Schedule-I; and
- (ii) working knowledge of Hindi written in Devnagri script and knowledge of Rajasthan Culture:

Provided that the person who has appeared or is appearing in the final year examination of the course which is the requisite educational qualification for the post as mentioned in these rules or Schedule for direct recruitment shall be eligible to apply for the post but he/she shall have to submit proof of having acquire the requisite educational qualification to the appropriate selection agency,-

- (i) before appearing in the main examination, where selection is made through two stages of written examination and interview;
- (ii) before appearing in interview where selection is made through written examination and interview; and
- (iii) before appearing in the written examination or interview, where selection is made through only written examination or only interview, as the case may be.

18. Character.- The Character of a candidate for direct recruitment to the service, must be such as to qualify him for employment in the service. He must produce a certificate of good character from the Principal /Academic Officer of the University or College or School in which he was last educated and two such certificates written not more than six months prior to the date of application, from two responsible persons not connected with his college or University or School and not related to him.

Note: (1) A conviction by a court of law need not itself involve the refusal of a certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association with crimes of violence or with a movement which has as its object to overthrow by violent means of the Government as by law established, the mere conviction need not be regarded as a disqualification.

- (2) Ex-prisoners who by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct have proved to be completely reformed should not

be discriminated against on grounds of their previous conviction for the purpose of employment in the service. Those who are convicted of offences not involving moral turpitude shall be deemed to have been completely reformed on the production of a report to that effect from the Superintendent, After Care Home or if there are no such Homes in a particular District, from the Superintendent of Police of that District.

- (3) Those convicted of offence involving moral turpitude shall be required to produce a certificate from the Superintendent, After Care Home or if there is no such Homes in a particular District, from the Superintendent of Police of that District, endorsed by the Director General of Police, Jail to the effect that they are suitable for employment as they have proved to be completely reformed by disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct in an After Care Home.

19. Physical Fitness.- A candidate for direct recruitment to the service must be in good mental and bodily health and free from any mental and physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of the services and if selected, must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose. The Appointing Authority may dispense with production of such certificate in the case of a candidate who is already serving in connection with the affairs of the State, if he has already been medically examined for the previous appointment and the essential standards of medical examination of the two posts held by him are held to be comparable for efficient performance of duties of the new post and his age has not reduced his efficiency for the purpose.

20. Employment of irregular or improper means.- A candidate who is or has been declared by the Board/Appointing Authority guilty of impersonation or of submitting fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or of suppressing material information or using or attempting to use unfair means in the examination or interview or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or appearance shall at any interview, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be debarred either permanently or for a specified period,-

- (a) by the Board/Appointing Authority from admission to any examination or appearance at any interview held by the Board/Appointing Authority for selection of candidates; and
- (b) by the Government from employment under the Government.

21. Canvassing.- No recommendation for recruitment either written or oral other than that required under these rules shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature by any means, may disqualify him for recruitment.

PART- IV

PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

22. Competitive examination, Authority for conducting examination and Syllabus for examination.- (1) Direct recruitment to the post included in the service shall be made through a written competitive examination in accordance with the scheme and syllabus of the examination as specified in Schedule-II.

(2) The examination for the post of Junior Electrical Inspector and for the post of Helper (Attached to Technical Post) in level-5 in Pay Matrix, as amended from time to time, shall be conducted by the Board or Appointing Authority, as the case may be.

23. Inviting of application.- Applications for direct recruitment to the post in the service shall be invited by the Board or Appointing Authority, as the case may be, by advertising the vacancies to be filled in, in the Official Gazette or in such other manner as they may deem fit. The advertisement shall contain a clause that a candidate who accepts the assignment on the post being offered to him/her shall be paid monthly fixed remuneration at the rate fixed by the State Government, from time to time, during the period of probation and Pay in Level of the Pay Matrix of the post as shown else-where in the advertisement shall be allowed only from the date of successful completion of the period of probation mentioned in these rules:

Provided that while selecting candidate for the vacancies so advertised the Board/ Appointing Authority may, if intimation of additional requirement not exceeding 50% of the advertised vacancies, is received before selection, also select suitable persons to meet such additional requirement.

24. Frequency of direct recruitment.- Direct recruitment to the post specified in the Schedule-I shall be held at least once a year unless the Government decides that a direct recruitment for any of these posts shall not be held in any particular year.

25. Form of application.- The application shall be made in the form approved by the Board or Appointing Authority, as the case may be and obtainable from office of the Board or Appointing Authority, as the case may be, on payment of such fee, as may be fixed by the Board or Appointing Authority, from time to time.

26. Application fee.- A candidate for direct recruitment to a post in the service must pay the fee fixed by the Board or Appointing Authority, in such manner as may be indicated by them/ it.

27. Scrutiny of applications.- The Board or Appointing Authority, as the case may be, shall scrutinize the applications received by it and require as many candidates qualified for appointment under these rules as seem to it desirable to appear in written examination:

Provided that the decision of the Board or Appointing Authority, as the case may be, regarding the eligibility or otherwise of a candidate shall be final.

28. Recommendation of the Board/Appointing Authority.- The Board or Appointing Authority as the case may be, shall prepare a list of the candidates, whom they consider suitable for appointment to the posts concerned, arrange their names in order of merit and forward the same to the Appointing Authority. The Board or Appointing Authority, as the case may be shall not recommend any candidate who has failed to obtain a minimum of 40% marks in written examination. However, relaxation in minimum marks upto 5% will be applicable to SC/ST category candidates:

Provided that the Board or Appointing Authority as the case may be, may to the extent of 50% of the advertised vacancies, keep names of suitable candidates on the reserve lists Category wise. Names of such candidates may, on requisition, be recommended in order of merit to the Appointing Authority within six months from the date on which the original list is forwarded by the Board or Appointing Authority.

29. Disqualifications for appointment.- (1) No candidate who has more than one spouse living, shall be eligible for appointment to the post in Service unless the Appointing Authority after being satisfied that there are special grounds permissible under personal law for doing so, exempt any candidate from the operation of this rule.

(2) No candidate who is married to a person having already a spouse living shall be eligible for appointment to the service unless the Appointing Authority, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any candidate from the operation of this rule.

(3) No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she at the time of his/her marriage or at any time there after, accepted any dowry.

Explanation: For the purpose of this rule “Dowry” has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act 28 of 1961)

(4) No candidate shall be eligible for appointment to the service who has more than two children on or after 01.06.2002:

Provided that,-

- (i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002 does not increase.
- (ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (iv) any person who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.
- (v) the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the appointment of a widow to be made under the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Deceased Government Servants Rule, 1996.

30. Selection by Appointing Authority.- Subject to the provision of rule 8, 9, 10, 11 and 12, the Appointing Authority shall select candidates in the order of merit in the list prepared under rule 28:

Provided that the inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that such candidate is suitable in all other respect for appointment to the post concerned.

PART – V

APPOINTMENT, SENIORITY, PROBATION AND CONFIRMATION

31. Appointment to the service.- Appointments to the post in the service by direct recruitment shall be made by the Appointing Authority on occurrence of substantive vacancies from the candidates selected under rule 28 in order of merit.

32. Urgent temporary appointment.- (1) A vacancy in the service which cannot be filled in immediately by direct recruitment under these rules, may be filled in by the Government or by the authority competent to make appointment, as the case may be, by appointing in an officiating capacity thereto a person eligible for appointment to the post by direct recruitment to the Service, where such direct recruitment has been provided under the provisions of these rules:

Provided that such an appointment shall not be continued beyond a period of one year without referring the case to the Government for concurrence, and shall be terminated immediately on its refusal to concur.

(2) In the event of non-availability of suitable persons fulfilling the requirement of eligibility, Government may, notwithstanding the condition of eligibility required under sub-rule (1) above, lay down general instructions for grant of permission to fill the vacancies on urgent temporary basis subject to such conditions and restrictions regarding pay and other allowances as it may direct. Such appointments shall, however, be subject to concurrence as required under the sub-rule (1) above.

33. Seniority.- Seniority of persons appointed to the post encadred in the service shall be determined from the date of appointment on the post after regular selection in accordance with the provisions of these rules. Appointment on ad-hoc or urgent temporary basis shall not be deemed to be appointment after regular selection:

Provided that,-

- (i) the seniority interse of persons appointed to a post in particular category by direct recruitment on the basis of one and the same selection, except those who do not join service when a post is offered to them, within a period of six weeks from the date of issue of order or longer, if extended by the Appointing Authority, shall follow the order in which they have been placed in the list prepared under rule 28;
- (ii) the person selected and appointed as a result of selection, which is not subject to review and revision, shall rank senior to the persons who are selected and appointed as a result of subsequent selection; and
- (iii) the seniority interse of the persons screened under proviso to sub-rule (3) of rule 6 shall be determined according to the length of continuous service after their irregular appointment. These persons shall rank junior

to the persons appointed regularly before the date of issue of their appointment order.

34. Period of Probation.- (1) A person entering the service by direct recruitment against a clear vacancy shall be placed as the probationer-trainee for a period of two years:

Provided that any period after such appointment during which a person has been on deputation on a corresponding or higher post shall count towards the period of probation.

(2) During the period of probation specified in sub-rule (1) above, each probationer-trainee may be required to pass such Departmental Examination and to undergo such training as the Government may, from time to time, specify.

35. Confirmation in certain cases.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the preceding rule, a person appointed to a post in the Service temporarily or on officiating basis who, after regular recruitment by any one of the methods of recruitment prescribed under these rules, has not been confirmed within a period of six months after satisfactory completion of the period of probation of two years service in case he/she is appointed by direct recruitment as a probationer-trainee or within a period of one year's service in case he/she is appointed by promotion, shall be entitled to be treated as confirmed in accordance with his/her seniority if,-

- (i) he/she has worked on the post or higher post under the same Appointing Authority or would have so worked but for his/her deputation or training ;
- (ii) he/she fulfils conditions as are prescribed under rule relating to confirmation subject to the quota prescribed under these rules; and
- (iii) permanent vacancy is available in the Department.

(2) If an employee referred to in sub rule (1) above, fails to fulfill the conditions mentioned in the said sub-rule, the period mentioned in sub-rule (1) above may be extended as prescribed for a probationer under the Rajasthan Civil Service (Departmental Examinations) Rules, 1959 and any other rules or by one year, whichever is longer. If the employee still fails to fulfill the conditions mentioned in sub-rule (1) above, he will be liable to be discharged or terminated from such post in the same manner as a probationer trainee or reverted to his substantive or lower post, if any, to which he may be entitled.

(3) The employee referred to in sub-rule (1) above, shall not be debarred from confirmation after the said period of service if no reasons to the contrary about the satisfactory performance of his work are communicated to him/her within the said period of service.

(4) The reasons for not confirming of any employee referred to in sub-rule (1) above, shall be recorded by the Appointing Authority in his Service Book and Annual Performance Appraisal Report.

Explanation: (i) Regular recruitment for the purpose of this rule shall mean,-

- (a) appointment by either method of recruitment or on initial constitution of service in accordance with the rules made under the proviso to Article 309 of the Constitution of India;
- (b) appointment to the post for which no service rules exist, if the post is within the purview of the Commission, recruitment in consultation with them;
- (c) appointment by transfer after regular recruitment where the service rules specifically permit; and

- (d) persons who have been made eligible for substantive appointment to a post under these rules shall be treated as having been regularly recruited:

Provided that it shall not include urgent temporary appointment which is subject to review and revision.

- (ii) Persons who hold lien on another cadre shall be eligible to be confirmed under these rules and they will be eligible to exercise an option whether they do not select to be confirmed on the expiry of two years of their temporary appointment under this rule. In the absence of any option to the contrary, they shall be deemed to have exercised option in favour of confirmation under this rule and their lien on the previous post shall cease.

36. Unsatisfactory progress during probation.- If it appears to the Appointing Authority, at any time, during or at the end of the period of probation, that services of a probationer-trainee are not found to be satisfactory, the Appointing Authority may revert him/her to the post on which he/she is regularly selected immediately preceding his/her appointment as probationer-trainee or in other cases may discharge or terminate him/her from service. The Appointing Authority shall accord appropriate opportunity to the probationer-trainee before final orders are passed in this respect:

Provided that the Appointing Authority may, if it so thinks fit in any case or class of cases, extend the period of probation of any probationer-trainee by a specified period not exceeding one year.

37. Confirmation.- A person placed on probation under rule 34 shall be confirmed in his/her appointment at the end of his/her period of probation, if,-

- (a) he/she has passed the Departmental Examination, and has successfully undergone such training as Government may, from time to time, specify;
- (b) he/she has passed departmental test of proficiency in Hindi; and
- (c) the Appointing Authority is satisfied that his/her integrity is unquestionable and he/she is otherwise fit for confirmation.

PART -VI

PAY

38. Scale of Pay.- The pay in the Level of the Pay Matrix (or amended from time to time) of a person appointed to a post in the service shall be such as may be admissible under the rules referred to in rule 40 or as may be sanctioned by the Government, from time to time.

39. Pay during probation.- A probationer-trainee appointed to the service by direct recruitment shall be paid monthly fixed remuneration during the period of probation at such rates as may be fixed by the Government, from time to time:

Provided that an employee having been regularly selected as per provisions of recruitment rules in the Government service may be allowed emoluments in his/her own Level in Pay matrix in the existing level in Pay matrix of the post during service as Probationer trainee or fixed remuneration of the new post, whichever is advantageous to him/her.

40. Regulation of pay, Leave, Allowances, Contributory Pension, Pension etc.-

Except as provided in these rules, the pay, allowances, pension, leave and other conditions of service of the members of the Service shall be regulated by,-

- (i) The Rajasthan Service Rules, 1951, as amended from time to time;
- (ii) The Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, as amended from time to time;
- (iii) The Rajasthan Travelling Allowance Rules, 1971, as amended from time to time;
- (iv) The Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971, as amended from time to time;
- (v) The Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, as amended from time to time;
- (vi) The Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998, as amended from time to time;
- (vii) The Rajasthan Civil Services (Contributory Pension) Rules, 2005, as amended from time to time;
- (viii) The Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, as amended from time to time;
- (ix) The Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, as amended from time to time; and
- (x) Any other rules prescribing general conditions of service made by the Appropriate Authority under the proviso to Article 309 of the Constitution of India and for the time being in force.

41. Power to relax rules.- In exceptional cases where the Administrative Department of the Government is satisfied that operation of the rules relating to age or regarding requirement of experience for recruitment causes undue hardship in any particular case or where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to relax any of the provisions of these rules with respect to age or experience of any person, it may with the concurrence of the Department of Personnel, by order, dispense with or relax the relevant provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner, provided that such relaxation shall not be less favourable than the provisions already contained in these rules. such cases of relaxation shall be referred to the Rajasthan Public Service Commission by Administrative Department concerned:

Provided that relaxation in the prescribed period of service or experience under this rule shall only be granted to the extent of 1/3 period of service or experience prescribed for promotion to any post before holding the meeting of Departmental Promotion Committee.

Provided further that where the prescribed period of experience for promotion to any post is less than 6 years, a committee headed by the Chief Secretary comprising of Principal Secretary Finance, Principal Secretary/ Secretary Department of Personnel and Principal Secretary/ Secretary of Administrative Department, may consider the cases where forty five percent or more post are vacant. The committee is empowered to suggest the quantum of relaxation in experience which may be granted in such cases to address the issue of large

number of vacancies in promotional posts subject to condition that such relaxation in experience shall not be more than two years.

42. Removal of doubts.- If any doubt arises relating to the application and scope of these rules, it shall be referred to the Government in the Department of Personnel whose decision thereon shall be final.

43. Repeal and Saving.- All rules and orders issued in relation to matters covered by these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any action taken under the rules and orders so repealed shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules.

Schedule-I

S.No.	Name of Post	Method of recruitment with percentage		Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
		Direct recruitment	Promotion				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Junior Electrical Inspector	100%	-	Degree in Electrical Engineering from a University established by law in India or Qualification declared equivalent by Government. OR Diploma in Electrical Engineering from a recognized institution.	-	-	-
2.	Helper (Attached to Technical Post)	100 %	-	Secondary with National Trade Certificate or ITI Certificate in Electrical Trade	-	-	-

Schedule-II

(A) Scheme & Syllabus of Written Competitive Examination to the post of Junior Electrical Inspector:

1. Computer based "Written Competitive Examination" shall be conducted through Online mode. The question paper shall be two hours duration and shall consist of Objective Type Questions (Multiple Choice Options) only.
2. The Question Paper shall consist of following two parts:-
Part A : 60% weightage
The standard and syllabus of the examination will be of the level of Diploma in Electrical Engineering and its brief out-line may be notified prior to the examination.

Part B : 40% weightage

- (i) Reasoning & Mental Ability
- (ii) Mathematics
- (iii) General Knowledge & Everyday Science
- (iv) Hindi General
- (v) English General

A brief out-line of scope of this part is given hereunder for general guidelines of candidates, but is not intended to be exhaustive:-

- (i) **Reasoning & Mental Ability :-** Analytical Reasoning, Number series, Letter series, Odd man out, Coding-Decoding, Shapes and Mirror Images, Clocks, etc.
 - (ii) **Mathematics :-** Mathematics (Class-XII level) CBSE or Rajasthan Board.
 - (iii) **General Knowledge & Everyday Science :-** Current events including issues of Rajasthan State, National & International importance, Persons & Places in recent news, Games & Sports, Science, Indian History, Civics, Geography, Indian Polity, etc., with special reference to Rajasthan.
 - (iv) **Hindi General :-** Hindi Grammar and language (Class-X level) CBSE or Rajasthan Board.
 - (v) **English General :-** English Grammar and language (Class-X level) CBSE or Rajasthan Board.
3. The Question Paper (except "Hindi General and "English General" section of part-B) shall be bilingual i.e. both in English & Hindi, but in case of any confusion/ambiguity with regard to interpretation or printing error, the English version of questions shall prevail.
 4. There will be no ' Negative ' marking for any wrong answer.
 5. If the examination is held in more than one session due to one or other reason, the scores across various sessions will be equated to adjust for slight differences in difficulty level of different test batteries used across sessions.

6. Appointing Authority/Board would analyse responses (answers) of individual candidates with those of other candidates to detect patterns of similarity of right and wrong answers. If it is inferred/ concluded that the responses have been shared and scores obtained are not genuine/ valid, Appointing Authority/Board reserves right to cancel the candidature of the concerned candidates and the result of such candidates (disqualified) will be withheld.
7. The scores of online exam will be obtained by adopting the following procedure :-
 - (i) Number of questions answered correctly by a candidate in the objective test is considered for arriving at the 'Corrected Score'.
 - (ii) The 'Corrected Scores' so obtained by candidates are made equivalent to take care of the minor difference in difficulty level, if any, in each of the objective tests held in different sessions to arrive at the 'Equated Scores'. Scores obtained by candidates on any test will be equated to the base form by considering the distribution of scores of all the forms.
 - (iii) Scores on total will be calculated with decimal point upto two digits.
8. Minimum passing marks for candidates in written examination shall be 40%. However, relaxation in minimum marks upto 5% will be applicable to SC/ST category candidates.
9. There shall be no 'interview'.

(B) Scheme & Syllabus of Written Competitive Examination to the post of Helper (Attached to Technical Post):

1. A written competitive examination shall be conducted. There shall be one question paper with Maximum 250 marks. Duration of the Paper will be 2.00 Hrs. The details of the question paper shall be as under:

Subject	Syllabus & Standard	Question	Max. Marks	Time
Part-A Gen. Awareness	Current Affairs, Gen. Science and Elementary Maths. Geography and Natural Resources, Agriculture & Economic Development. History & Culture with special emphasis on Rajasthan	50	50	2.00 Hrs
Part- B Tech. Knowledge / Skill	The standard and syllabus will be the level of ITI in the trade of Electrical.	100	200	

2. The question paper shall consist of 'Objective Type Question (multiple choice options) of answer. In Part - A each question will carry one mark and in Part - B each question will carry two marks. The question paper will be bilingual i.e. Hindi and English. There shall not be negative marking.
3. The selection of candidate will be based on the marks, secured in written competitive examination.
4. Minimum passing marks for candidates in written examination shall be 40%. However, relaxation in minimum marks upto 5% will be applicable to SC/ST category candidates.

5. There shall be no interview.
6. In case two or more candidate secure equal marks in written competitive examination, their merit shall be decided as per their date of birth i.e. elder candidate shall be placed higher in the merit list.

[F.1(3)DOP/A-II /2020]

**By Order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

Government Central Press, Jaipur.